भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1865 का उत्तर

लंबित रेल परियोजनाएं

1865. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक, राज्यों द्वारा प्रस्तुत नई रेल परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) नई/चालू/लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और सर्वेक्षण की स्थिति क्या है और इनकी राज्य-वार और परियोजना-वार स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में आवंटित किए गए/उपयोग की गई निधि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समय पर पूरा न होने के कारण परियोजनाओं की लागत में तीव्र वृद्धि हुई है और यदि हां, तो आज की तिथि में अधूरी परियोजनाओं की संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

mm

लंबित रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 03.07.2019 को लोक सभा में श्री गोपाल शेट्टी के अतारांकित प्रश्न सं. 1855 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): रेल परियोजनाओं के लिए, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों, प्रस्ताव/ सुझाव/अभ्यावेदन रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडलों आदि सहित रेलवे के विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, चुने हुए प्रतिनिधियों, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि, से प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्तावों/सुझावों का प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इन अनुरोधों का केन्द्रीकृत संग्रह नहीं रखा जाता। नई लाइनों, मीटर आमान का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन आदि भारतीय रेल की एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये कार्य राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांग और रेलवे की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर किए जाते हैं।

(ख): इस समय, 189 नई लाइनों, 55 आमान परिवर्तन और 247 दोहरीकरण परियोजनाओं सहित 491 रेल परियोजनाएं निष्पादन/नियोजन/स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 48860.64 कि.मी. और लागत 6.476 लाख करोड़ रुपए है।

गत तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा 272 अदद रेल परियोजनाओं (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण कार्य) के लिए सर्वेक्षण शुरु किए गए जिनकी कुल लंबाई 26954 कि.मी. है।

(ग): मार्च 2019 तक, उपर्युक्त 491 परियोजनाओं के लिए 1.43 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया। बहरहाल, प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई धनराशि, धन का आबंटन और व्यय का ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और यह ब्यौरा निर्माण कार्यों, मशीनरी और चल स्टॉक कार्यक्रम (पिंक बुक) में भी उपलब्ध होता है जो भारतीय रेल की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ): किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का अंतरण (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर), विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, परियोजना के शीघ्र निष्पादन के लिए राज्य सरकार का सहयोग और उत्साह, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल, माननीय न्यायालय के आदेश जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति

और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना की निष्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंत में पूरा होने की स्थिति पर गणना की जाती है।

समग्र राष्ट्रहित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना बिना लागत में वृद्धि के पूरी हो जाए, रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और बोर्ड स्तर) पर काफी निगरानी की जाती है और परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय से पहले भी पूरी हो जाती हैं, रेलवे ने निविदा में बोनस क्लॉज के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहन की अवधारणा को अपनाया है जो परियोजना के निष्पादन की गति में और वृद्धि करेगा।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता आदि के लिए मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड से 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

******

mm